बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 170 ● नई दिल्ली ● शनिवार 05 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

पीसीआई अध्यक्ष मोंटू पटेल के ठिकानों पर छापेमारी; फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देने में भ्रष्टाचार का आरोप

नई दिल्ली । सीबीआई ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के अध्यक्ष मोंटू एम पटेल के परिसरों पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि मोंटू एम पटेल ने फार्मेसी कॉलेजों के निरीक्षण और अनुमोदन प्रक्रियाओं में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया गया है। पटेल के खिलाफ यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच (पीई) के निष्कर्षों के आधार पर की गई है। जांच के दौरान पता चला था कि उन्होंने कॉलेजों को मंजूरी देने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार, नियंत्रण और हेरफेर किया।

दिल्ली में फूलकुमारी निवास पर कांग्रेस का वार, जनता गर्मी से बेहाल, सीएम रेखा "फूलकुमारी निवास" को राजमहल में तब्दील करने में व्यस्त

नारी सुरक्षा पर चुप्पी, लेकिन बंगले में सीसीटीवी लगवाना प्राथमिकता- देवेंन्द्र

नई दिल्ली । दिल्ली में केजरीवाल सरकार के सरकारी आवास शीशमहल को लेकर काफी विवाद हुआ था. विपक्षी दलों ने इसे लेकर खूब हंगामा किया था, अब कुछ ऐसा ही हाल बीजेपी की रेखा सरकार में देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए फूलकुमारी निवास बनाया जा रहा है. इस पर हो रहे खर्च को लेकर कांग्रेस ने कड़े सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीति फिर से गरमा गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने रेखा गुप्ता पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जब राजधानी की जनता बिजली कटौती, जल संकट और जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है, तब मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास "फूलकुमारी निवास" को राजमहल में तब्दील करने में व्यस्त हैं. उन्होंने खुलासा किया कि बंगला संख्या-1 (राज निवास मार्ग) के नवीनीकरण का खर्च सिर्फ एक चरण में ही 59.40 लाख रुपये तक पहुंच गया है. इसमें 11 लाख रुपये एयर कंडीशनिंग और 6 लाख रुपये लाइट्स एवं झूमरों पर खर्च हो रहे हैं. इसके अलावा 2 लाख रुपये का विशेष गैर बाधित बिजली सिस्टम भी लगाया जा रहा है. यादव ने मुख्यमंत्री पर जनता की समस्याओं की अनदेखी और सार्वजनिक मर्यादा की अवहेलना का

आरोप लगाते हुए कहा कि, जब राजधानी की जनता भीषण गर्मी, गंदे पानी और असुरक्षा से जूझ रही है, उस समय मुख्यमंत्री का यह खर्च गैर-जिम्मेदाराना रवैये, असंवेदनशीलता और सत्ता के अहंकार को दर्शाता है. यह जनभावनाओं की खुली उपेक्षा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. देवेन्द्र यादव ने कहा कि, मुख्यमंत्री आवास पर यह खर्च आगे और बढ़ेगा. उन्होंने याद दिलाया कि केजरीवाल सरकार ने भी 'शीशमहल' के नाम पर 110 करोड़ रुपये खर्च कर जनता की पीठ में छुरा घोंपा था. अब बीजेपी सरकार भी उसी राह पर चलती दिख रही है, जहां जनता की मूलभूत जरूरतों की जगह व्यक्तिगत विलासिता प्राथमिकता बन गई है. यादव ने पूछा, 'जब राजधानी की लाखों आबादी नलों से गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर है, तब मुख्यमंत्री के बंगले में आरओ सिस्टम लगाना क्या जनता के साथ क्रूर मजाक नहीं है?' उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मुख्यमंत्री खुद नल का पानी नहीं पी सकतीं तो जनता से 'वाटर टेस्टिंग लैब' के नाम पर पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? महिला सुरक्षा को लेकर भी यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने आवास में 5.74 लाख रुपये की लागत से 14 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए टेंडर निकाला है, जबकि बजट में घोषित 50,000 सीसीटीवी कैमरों की कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पर बयानबाजी तो होती है, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता. यादव ने खुलासा किया कि आवास में 9.3 लाख रुपये की लागत से पांच टेलीविजन लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक विशेष 165 सेमी का टीवी केवल मुख्यमंत्री के लिए है. साथ ही 14 एयर कंडीशनर 7.76 लाख रुपये में लगाए जा रहे हैं, जिनकी वारंटी पांच साल की है. तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा, तो बीजेपी के अंदर ही असंतोष की लहर उठेगी और पार्टी के सांसद-विधायक उन्हें वारंटी पीरियड से पहले ही बदल देंगे.

दिल्ली मेसीएम जन सेवा सदन का उद्घाटन, बीजेपी बोली- पहले के मुख्यमंत्री शीशमहल बनाते थे और हम जनसेवा केंद्र

नई दिल्ली ।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री आवास पर नए कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि मैं दिल्ली की सीएम को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह लोगों और उनकी समस्याओं के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। आने वाले समय में दिल्ली के लोगों की समस्याओं और दुखों का समाधान सीएम आवास से किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतें सुनने के लिए जो केंद्र बनाया है, उसका आज उद्घाटन हो रहा है। मैं अपनी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री शीशमहल बनाते थे और लोगों को अपने आवास में प्रवेश नहीं

करने देते थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने जनसेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। यह मुख्यमंत्री जनसेवा केंद्र आम लोगों को मुख्यमंत्री आवास में आने की सुविधा देने के लिए बनाया गया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बार-बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास अब जनसेवा सदन के नाम से जाना जाएगा। यहां एक शीशमहल था जहां किसी भी कैमरे पर प्रतिबंध था (दिल्ली में आप सरकार के दौरान), और यहां हमने आवास को जनसेवा सदन में बदल दिया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के 'जन सेवा सदन' के उद्घाटन की सराहना की और कहा कि इसकी लागत अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगे पर्दों की लागत से भी कम है। कपिल मिश्रा ने बताया कि 'जन सेवा सदन' कैमरों और मीडियाकर्मियों के लिए खोला गया है, ताकि वे आम लोगों के लिए की गई व्यवस्था देख सकें। दिल्ली के मंत्री ने बताया कि 'जन सेवा सदन' के लिए टेंडर सार्वजनिक है, जबकि 'शीश महल' के टेंडर दस्तावेज में ऐसा नहीं है। कपिल मिश्रा ने एएनआई से कहा, मुख्यमंत्री के जन सेवा सदन का आज उद्घाटन हुआ है। आज पहला दिन है। यह मीडिया और कैमरों के लिए खुला है, ताकि आम लोगों के लिए की गई सभी व्यवस्थाओं को देखा जा सके।

11 साल बाद सीएम का आवास या कार्यालय लोगों के लिए खोला गया है... पूरा जन सेवा सदन अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लगे पर्दों की कीमत से भी कम लागत में बना है... शीश महल के टेंडर डॉक्यूमेंट से अलग इसका टेंडर डॉक्यूमेंट भी सार्वजनिक है... दिल्ली के लोगों की सभी शिकायतें यहां सुनी और दर्ज की जाएंगी।

बवाना हत्याकांड : गैंगस्टर मनजीत महाल के भांजे की हत्या की गुत्थी सुलझी, नंदू गैंग के दो शूटर गिरफ्तार

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर मनजीत महाल के भांजे दीपक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नंदू गैंग के दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर पांच राउंड फायरिंग की, इसके जवाब में पुलिस ने भी चार राउंड की फायरिंग की। पुलिस को मौके से दो देसी पिस्टल और आठ कारतूस बरामद मिले हैं। पकड़े गए बदमाशों का नाम विजय और सोमवीर बताया जा रहा है। दोनों ही कुख्यात नंदू गैंग से जुड़े शूटर हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि ये दोनों शूटर गैंगस्टर मनजीत महाल के भांजे दीपक की हत्या में शामिल थे। पकड़े गए बदमाशों में से सोमवीर उर्फ चिनू, निवासी खेड़ी जलीब, हिसार (हरियाणा), बवाना थाने में दर्ज दीपक हत्या के केस में मुख्य शूटर है। वहीं, दूसरा शूटर विजय, निवासी भास्कर कॉलोनी, सेक्टर 25डी, चंडीगढ़, कई पुराने आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। इसने शूटरों को शरण देने और रसद मुहैया कराने का काम किया था। बता दें कि 27 जून को बवाना में मनजीत महाल के भांजे दीपक पर उस समय हत्या हुई थी जब वो सुबह के वक्त अपनी बेटी के साथ घूमने निकले थे। उन्हें करीब छह गोलियां मारी गई थीं। गोलीबारी में उनकी बेटी घायल हो गई थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा: भारत अपनी स्पेस सफलताओं को विश्व के साथ साझा कर रहा है

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग स्थल का नाम 'शिव शक्ति बिंदु' रखे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस समय एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद है और हम 'गगनयान' नाम के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहे हैं। जल्द ही एक भारतीय चंद्रमा पर कदम रखेगा और भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भी होगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत

अपनी अंतरिक्ष सफलताओं को विश्व के साथ साझा कर रहा है। मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में बसे भारतीय समुदाय की भूमिका की भी सराहना की और उन्हें 'राष्ट्रदूत' बताया। उन्होंने कहा, हम अपने प्रवासी भारतीयों की ताकत और समर्थन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। दुनिया भर में 3.5 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय भारत की संस्कृति, मूल्यों और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का भी जिक्र किया, जिसमें त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू मुख्य अतिथि थीं। उन्होंने बताया कि भारत गिरमिटिया समुदाय के इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न पहलों पर काम कर रहा है। मोदी ने कहा, हम गिरमिटिया समुदाय के गांवों और शहरों का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं जहां से उनके पूर्वज भारत से गए थे। इसके साथ ही, हम 'विश्व गिरमिटिया सम्मेलन' आयोजित करने की योजना भी बना रहे हैं, जिससे हमारे ऐतिहासिक और भावनात्मक रिश्ते और मजबूत होंगे।

दिल्ली में दिव्यांग पार्क को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस योजना के तहत 90 लाख रुपये में बना; ओपन जिम भी मिलेगा

पूर्वी दिल्ली।

पूर्वी दिल्ली में यमुनापार के पहले दिव्यांग पार्क को खुलने में वक्त लगेगा। अब इसमें एसटीपी बनाने का प्रविधान किया जा रहा है। इस कार्य में छह माह से अधिक का समय लग सकता है। क्योंकि अभी एसटीपी बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति लेने की प्रक्रिया में है। यहां सवाल यह है कि एक साल से तैयार इस पार्क में पहले इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया। पहले ही एसटीपी बनवा दिया होता तो लोगों के लिए पार्क खोला जा सकता था। टिंबर मार्केट वाली लोनी रोड स्थित दो एकड़ के भूखंड पर दिव्यांग पार्क बना है। इसमें प्रवेश से लेकर अंदर घूमने के लिए पैदल पथ तक दिव्यांगों के अनुकूल बनाए गए हैं। प्रवेश द्वार पर सीढ़ी के साथ रैंप है, ताकि पैरों से दिव्यांग व्हीलचेयर पर बैठकर आसानी से अंदर जा सकें। दृष्टिबाधितों के लिए पैदल पथ पर पीले रंग के स्पर्शीय टाइल्स लगाए हैं, जिसके जरिये वह आसानी से चल सकेंगे। बैठने के लिए बेंच लगे हैं। बताया गया कि गजीबो यानी झोपड़ी आकार में बैठक भी बनाई है। सुंदरता के लिए फूलों से लेकर सजावटी पौधे लगाए गए हैं। इसमें उनके लिए ओपन जिम भी है। जिम के उपकरण दिव्यांगों के अनुकूल हैं। इसमें चेस्ट प्रेस, आर्म एक्सटेंशन, आर्म साइकिल, पुलअप रैक, आर्म एक्सरसाइजर समेत कई उपकरण लगे हैं। अमृत योजना के तहत करीब 90 लाख रुपये की लागत से यह बना है। शाहदरा उत्तरी जोन के उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पार्क को एसटीपी बनने के बाद खोला जाएगा। एसटीपी की करीब 20 केएलडी होगी। दिव्यांग बच्चों के मनोरंजन के लिए इस पार्क में पूरी व्यवस्था है। एक हिस्से में अलग-अलग तरीके के वाद्य यंत्र लगाए गए हैं। बच्चे इस हिस्से में आकर वाद्य यंत्र बजाना सीख सकेंगे। इन यंत्रों में कांगो ड्रम, बाबेल ड्रम (छोटे व बड़े), पैपिलियो बेल, फ्री चाइम्स, रेनबो सांबा, कांगो आदि शामिल हैं। झूले भी इनको ध्यान में रखकर लगाए हैं। उनमें सुरक्षा बेल्ट का प्रविधान है। इनमें व्हील चेयर स्विंग, सीटर स्विंग, सीटर स्प्रिंग सी-सा, ईंटर एमजीआर झूला लगा है।

राज्यपाल की वीसी नियुक्तियों की भूमिका घटाने वाले कानून पर हाई कोर्ट की रोक को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु के राज्यपाल कार्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने वाले कानूनों पर रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ द्वारा 21 मई को पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में राज्यपाल, जो कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हैं, की भूमिका को कम करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय कानूनों में संशोधन करने वाले हाल के राज्य कानून के संचालन पर रोक लगा दी थी। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, राकेश द्विवेदी और पी विल्सन ने सर्वोच्च न्यायालय से यह स्पष्ट करने

का भी आग्रह किया कि मद्रास उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चुनौती के बावजूद 14 जुलाई को रोक हटाने के लिए उसके आवेदन पर सुनवाई कर सकता है। हालांकि, यूजीसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि तमिलनाडु ने भी सभी संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक स्थानांतरण याचिका दायर की है। मेहता ने तर्क दिया कि आप मामले को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग नहीं कर सकते और साथ ही उच्च न्यायालय से आदेश के लिए दबाव नहीं बना सकते। उन्होंने कहा कि राज्य के कानून यूजीसी के नियमों के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। पीठ ने इस पहलू पर कोई भी राय व्यक्त करने से परहेज किया और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य की याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी करने तक ही खुद को सीमित रखा। उच्च न्यायालय का 21 मई का फैसला एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर आया था, जिसने राज्य के संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कानून यूजीसी के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो केंद्रीय प्रकृति के हैं और अनिवार्य करते हैं कि कुलपतियों की नियुक्ति कुलाधिपति - राज्यपाल द्वारा की जानी चाहिए।

हिमाचल-उत्तराखंड समेत कई राज्यों के सीएम से शाह ने की बात; आफत की बारिश से मची तबाही पर चर्चा

नई दिल्ली । देशभर में हो रही भारी बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पहाड़ों पर मची तबाही और कुछ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात के बीच शाह ने सभी को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, देश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश के मद्देनजर गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की। जरूरतमंद लोगों के लिए राज्यों में पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर और भी बल भेजा जाएगा। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, मकान मालिकों को राहत, पुराने किराएदार अब नहीं कर पाएंगे ये काम?

नई दिल्ली । अगर आप दिल्ली में रहते हैं और मकान मालिक हैं और आपके किराएदार आपको मकान खाली करने को लेकर परेशान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने मकान मालिकों से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी किया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को एक पुराना और दुरुपयोग किया गया कानून करार देते हुए एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि इस कानून के दुरुपयोग से संपत्ति मालिकों को गंभीर आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि संपन्न किरायेदार दशकों से मामूली किराए पर कीमती संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं. जस्टिस अनुप जयराम भम्भानी ने यह टिप्पणी सदर बाजार स्थित एक संपत्ति से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए की. इस मामले में यूके और दुबई में बसे संपत्ति मालिकों ने 2013 में अपने किरायेदारों को हटाने की मांग की थी जिसे रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ने खारिज कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने देखा है कि बहुत से मामले ऐसे हैं, जहां आर्थिक रूप से मजबूत किरायेदार सालों से प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए बैठे हैं जबकि मकान मालिक आर्थिक रूप से तबाह हो गए हैं. यह सब दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जैसे पुराने कानून के दुरुपयोग का नतीजा है. घर के मालिकों ने यह दलील दी थी कि वे लंदन में दो रेस्टोरेंट चलाते हैं और अब भारत में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं. ARC ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि उन्हें उस संपत्ति की जीविकोपार्जन के लिए जरूरत नहीं है और वह छोटी जगह रेस्टोरेंट के लिए उपयुक्त नहीं. हाई कोर्ट ने रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के फैसले को पलटते हुए अपने आदेश में कहा कि किरायेदार की आर्थिक स्थिति या मालिक की संपन्नता इस मामले में कोई महत्व नहीं रखती. मालिक अपने व्यापार का विस्तार एक छोटे ठिकाने से करे या बड़े रेस्टोरेंट से यह उसका विशेषाधिकार है . हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 14(1)(e) के तहत यह देखना जरूरी नहीं है कि मालिक भारत में रहता है या विदेश में, बल्कि यह देखा जाता है कि उसका प्रॉपर्टी को लेकर वास्तविक और ईमानदार उद्देश्य है या नहीं.

दिल्लीवाले पानी के बिलों से ना हो परेशान, नहीं कटेगा कनेक्शन; सरकार लाखों लोगों को देने जा रही है राहत

नई दिल्ली। पानी के अधिक बिल से परेशान उपभोक्ताओं को दो माह के बाद राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के जल मंत्री ने कहा, इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अगले दो माह में सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस योजना में घरेलू व सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस योजना के आने तक किसी भी उपभोक्ता का पानी का कनेक्शन नहीं कटेगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ एक बार ही बकाया बिल माफी योजना का मौका मिलेगा। बाद में उन्हें पूरा बिल देना होगा। पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार के समय से पानी के अधिक बिल की समस्या चली आ रही है। आप सरकार ने भी बिल माफी योजना की घोषणा की थी लेकिन वह लागू नहीं हुआ था। दिल्ली में लगभग 27 लाख पानी के कनेक्शन हैं। कोरोना काल में मीटर की रीडिंग ठीक से नहीं हुई और उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल भेज दिया गया। उपभोक्ताओं की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं को पानी के अधिक बिल भेजे गए हैं। बिल भुगतान नहीं होने से जल बोर्ड को भी 1300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। मंत्री ने प्रेसवार्ता में कहा, दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में एशियन विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से वजीराबाद जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) कमांड एरिया में दिल्ली जल आपूर्ति सुधार योजना को दोबारा शुरू करने को मंजूरी दी है। वर्ष 2013 में 2433 करोड़ रुपये की यह परियोजना स्वीकृत हुई थी लेकिन जुलाई 2020 तक टेंडर जारी नहीं हुआ, जिससे एडीबी ने पैसा नहीं दिया। अब जल मंत्री के प्रयास से एडीबी ने फंड देने पर सहमति दी है। इससे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, मॉडल टाउन, बुराड़ी, पंजाबी बाग, पीतमपुरा सहित अन्य क्षेत्रों के लगभग 30.16 लाख लोगों को लाभ होगा। इस योजना के अंतर्गत 24×7 जल आपूर्ति, गैर राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को 15% तक लाने का लक्ष्य है। अब इस परियोजना की लागत 3715 करोड़ रुपये हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भूमि विकास एजेंसियों की पेयजल व सीवर योजनाओं को स्वीकृत करने और उन्हें क्रियान्वित करने की अनुमति दी गई है। इससे लोगों को समय पर आवास उपलब्ध होगा। जल बोर्ड को राजस्व भी मिलेगा। पूर्व सरकार की गलत नीति के कारण कठपुतली कालोनी पुनर्वास सहित अन्य परियोजनाओं में विलंब हुआ। सोनिया विहार श्रीराम कॉलोनी में 69.97 करोड़ की लागत से 66 किमी और हमनपुर के आठ गांवों व दो अनधिकृत कालोनियों में 51.43 करोड़ रुपये की लागत से 50 किमी सीवर लाइन बिछेगी। जल बोर्ड में युवा अभियंताओं की भर्ती की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र व केंद्र व राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अभियंताओं को सलाहकार के रूप में भर्ती की जा रही है, इन्हें कोई वित्तीय अधिकार नहीं होगा।

संविधान से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 'समाजवादी' और 'पंथ निरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा होनी चाहिए। उनका कहना है कि यह शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे और बाद में इंदिरा गांधी की इमरजैंसी के दौरान 1976 में 42वें संशोधन से इन्हें जोड़ा गया। इन्हें तब जोड़ा गया जब मूल अधिकार छीन लिए गए थे, संसद ठप्प थी और न्यायपालिका पंगु हो चुकी थी। कांग्रेस ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि आरएसएस का नकाब फिर उतर गया और इन्हें अम्बेडकर का संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए। लेकिन क्या वाकई संविधान में परिवर्तन करने की कोशिश हो रही है? जो होसबाले ने कहा वह ट्रायल बलून था,लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए छोड़ा गया था? भाजपा के शीर्ष नेता तो चुप है पर केन्द्रिय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा है कि भाजपा संविधान की प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' हटाने का समर्थन करती है। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि संविधान से इन दो शब्दों को हटाने पर विचार होना चाहिए। पर उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने जो कहा वह तो घोर चिन्ता पैदा करता है कि देश को किस तरफ धकेला जा रहा है? महामहिम कहते है, संविधान की प्रस्तावना बहुत पवित्र है। पर इसमें धर्म निरपेक्ष और समाजवाद जोड़े गए,यह ऐसा बदलाव था जो अस्तित्वगत संकट को जन्म देता है। यह शब्द नासूर है। यह उथल पुथल पैदा करेंगे,यह सनातन की आत्मा का अपवित्र अनादर है। उपराष्ट्रपति को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है पर एक शब्द चुभता है, नासूर ! क्या देश के उपराष्ट्रपति सचमुच समझते हैं कि धर्म निरपेक्षता और समाजवाद 'नासूर' है? 50 वर्ष से यह चल रहे है इससे क्या उथल-पुथल पैदा हुई है? और क्या अगर इन्हें हटा दिया जाए तो देश की सारी समस्याएं, रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, रोजगार, चीन-पाक आदि हल हो जाएंगी? इंदिरा गांधी द्वारा लगाई इमरजैंसी देश पर सदा एक कलंक रहेगी। खुद की कुर्सी बचाने और पुत्र संजय गांधी, जो खुद को सरकार से भी ऊपर समझने लगा था, की रक्षा करने के लिए उन्होंने देश को कैदखाने में परिवर्तित कर दिया। 1.2 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी सब छीन लिए गए। अख़बारों पर सैंसर बैठा दिया गया और 250 पत्रकारों को गिरफ्तार कर दिया गया जिनमें लाला जगत नारायण और रमेश जी भी शामिल थे। प्रताप और वीर प्रताप ने जब खाली जगह छोड़नी शुरू की तो सैंसर ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। कई अख़बारों ने प्रतिरोध किया पर बहुत ने समर्पण कर दिया जिस पर लालकृष्ण आडवाणी का कटाक्ष आज तक प्रसिद्ध है कि जब इन्हें झुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने रेंगना बेहतर समझा। दिलचस्प है कि जहां आरएसएस के कार्यकर्ता जेपी आन्दोलन की रीढ़ की हड्डी थे संघ प्रमुख बाला साहेब देवरस के विचार अलग थे। उन्होंने जेल से इंदिरा गांधी को प्रशंसा के पत्र लिखे। जब यह भी सफल नहीं हुआ तो उन्होंने विनोबा भावे को पत्र लिखा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कि प्रधानमंत्री के मन में संघ के बारे जो गलत प्रभाव है उसे हटाने की कोशिश करें ताकि संघ पर बैन हट सके और कार्यकर्ता जेल से छूट सकें,और प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अधीन,प्रगति में योगदान डाल सकें। अर्थात् तत्कालीन संघ प्रमुख इमरजैंसी के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार थे। उन्हें 'समाजवाद' या 'धर्म निरपेक्षता' से भी कोई समस्या नहीं थी। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने यह सारा प्रसंग अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टरज़ डिसाइड में बताया है। इस बात की पुष्टि अभिषेक चौधरी अपनी किताब वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिन्दू राइट में करते है, देवरस ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों को पुणे के यरवदा जेल से दो-दो पत्र लिखे थे,जिनमें विनती की गई थी कि संघ से प्रतिबंध हटा लिया जाए और सरकार को अपनी संस्था की सेवाएं देने की पेशकश की। जैसे ज्योत्सना मोहन और मैंने अपनी किताब प्रताप ए डिफायंट न्यूज़ पेपर में लिखा है, इस बात की अनदेखी की जाती है कि केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं, संघ के लिए भी यह असुखद अध्याय था। इंदिरा गांधी ने इमरजैंसी क्यों लगाई? 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के दो हिस्से करवा बंगलादेश का निर्माण करवाया था। लोकप्रियता चरम पर थी यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें 'दुर्गा' का रूप कहा था। पर उसके बाद संकट पर संकट आता गया। युद्ध का खर्चा, अकाल और तेल संकट से लोगों की मुश्किल बहुत बढ़ चुकी थी। पूर्व प्रधानमंत्री इन्द्र कुमार गुजराल जो उस वक्त सूचना और प्रसारण मंत्री थे और जिन्हें संजय गांधी के कहने पर हटा दिया गया था, ने बताया था कि ,इंदिरा गांधी को समझ नहीं आ रहा था कि असंतोष की उठती लहर से कैसे निपटें। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की यह पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, को लेकर जयप्रकाश नारायण ने देश भर में आन्दोलन खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी का दुर्भाग्य है कि उसी वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा ने चुनावी दुराचार के आरोप में रायबरेली से चुनाव को रद्द कर दिया। यह निर्णय 12 जून 1975 को दिया गया। इंदिरा गांधी अपने छोटे पुत्र संजय के प्रभाव में आ गईं और तेरह दिन के बाद 25 जून को देश में इमरजैंसी लागू कर दी गई। जिस तरह अचानक इमरजैंसी लगाई गई उसी तरह अचानक इसे हटा कर चुनाव की घोषणा कर दी गई। अचानक ऐसे क्यों किया गया जबकि क़ानूनी तौर पर लोकसभा के पन्द्रह महीने बाकी थे? संजय गांधी चुनाव करवाने के बिल्कुल विरुद्ध थे पर इंदिरा ने चुनाव करवाने का मन बना लिया था। नीरजा चौधरी अपनी किताब में लिखती है संजय की बढ़ती ताक़त और अलोकप्रियता, उनका अपना कमजोर होता मताधिकार, अंतर्राष्ट्रीय राय, आंतरिक दबाव, उनकी अपनी बेचैनी,उन्होंने फ़ैसला किया कि चुनाव करवाने में ही बेहतरी है। इतिहासकार ज्ञान प्रकाश लिखते है कि ,इंदिरा गांधी अपने शासन की वैधता चाहती थी और उनका विचार था कि चुनाव उनके शासन को वैधता देगा। मेरा अपना मानना है कि उनके मन में यह भी था कि वह जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है और वह परिवार की विरासत को मिट्टी में मिला रही है। चुनाव हुए और वह बुरी तरह से हार गईं। देश की पहली गैर-कांग्रेस सरकार का गठन किया गया,इंदिरा और संजय दोनों हार गए। लेकिन जनता पार्टी के नेता सम्भाल नहीं सके। अपनी-अपनी ईगो के कारण सरकार लड़खड़ाने लगी। चुनाव की नौबत आगई और इमरजैंसी लगाने के तीन वर्ष बाद ही 1980 में फिर इंदिरा गांधी सत्तारूढ़ हो गईं। आरएसएस का संविधान से रिश्ता भी उल्लेखनीय है। जिस वक्त संविधान को स्वीकार किया गया, संघ प्रमुख गोलवालकर ने इसे मानने से इंकार कर दिया था। उनकी शिकायत थी कि इसमें मनुस्मृति से कुछ नहीं लिया गया। वह हिन्दू राष्ट्र चाहते थे। गोलवालकर ने इसे पश्चिमी विचारों का पुलिंदा कहा था। लेकिन बाद में संघ ने इससे समझौता कर लिया, पर कुछ दुराव रह गया जो दत्तात्रेय होसबाले के कथन से पता चलता है। यह सही है कि प्रस्तावना में जो दो शब्द जोड़े गए वह इमरजैंसी के दौरान जब देश कैदखाना था, जोड़े गए। पर इन्हें देश की जनता ने स्वीकार किया है। जनता पार्टी की सरकार ने भी 42वें संशोधन से कई चीजें हटा दी थी पर इन दो शब्दों को हाथ नहीं लगाया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन दो शब्दों को आम स्वीकृति मिली हुई है और 'हम भारत के लोग' स्पष्ट तौर पर इनका मतलब समझते है।

यह वैध है।

1973 में केशवानन्द भारती मामले पर अपने लैंडमार्क फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 'सेक्यूलरिज़म संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है'। और समाजवाद जो सबको बराबरी देता है पर आपत्ति क्या है? क्या वह पूंजीवाद चाहते है? जहां इतनी गरीबी हो वहां और कौनसा 'वाद' चलेगा? सरकार कोई भी आर्थिक नीति बना सकती है, प्रस्तावना तो बाधा खड़ी नहीं करती। इस वक्त देश के 1 फीसदी के पास 50 फीसदी सम्पत्ति है। एक शताब्दी में सबसे अधिक असमानता आज है। सरकार को संतुलन सही करने से कौन रोकता है? सैक्यूलर का अर्थ है कि सरकार की कोई भी नीति धर्म के आधार पर तय नहीं होगी। धर्म के मामले में सरकार न्यूट्रल है। हमारी संस्कृति उदार और सहिष्णु है जो बात स्वामी विवेकानन्द ने भी बार बार कही है,पर इससे भी महत्वपूर्ण है कि भारत की जनता को समाजवाद और धर्म निरपेक्षता से कोई ?दिक्कत नहीं। भाजपा को तो वैसे भी सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि अगर यह प्रभाव फैल गया कि वह संविधान बदलना चाहते है तो बहुत बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ सकती है।

आस्था की कांवड़ पर 'नफ़रती गैंग' का कब्ज़ा

मुकुल सरल

दोस्तो, सावन आ रहा है, कांवड़ यात्रा एक बार फिर शुरू हो रही है, लेकिन अब इसके साथ आस्था, भक्ति या उत्साह से ज्यादा डर और आशंकाएं मन में घर करने लगती हैं। और यह डर यूं ही नहीं है, इसकी फिर शुरुआत हो गई है। पिछले साल तो हिंदू-मुस्लिम को लेकर नेमप्लेट का ही विवाद शुरू हुआ था इस बार तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर लोगों की पैंट ही खुलवाई जाने लगी है। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। यह महीना शिवभक्ति का महीना माना जाता है। 23 जुलाई को शिवरात्रि का त्योहार है। इस पूरे महीने शिवभक्त हरिद्वार समेत विभिन्न नदियों से पवित्र जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मैं भी इसका साक्षी रहा हूं। किशोर अवस्था तक मैंने भी खूब कांवड़ उठाई है। हरिद्वार से कांवड़ लाने वाले कई परिजनों का बीच रास्ते में सहायक बना हूं। आज आप मुझे नास्तिक कह सकते हैं, लेकिन शिव आज भी मुझे बहुत प्रिय हैं। धार्मिक रूढ़ियों से अलग वे मुझे लोक के देवता लगते हैं। अपने से लगते हैं। देवता से ज्यादा एक जीवन दृष्टि। जिसमें तप, प्रेम, त्याग, न्याय, ध्यान, करुणा का प्रमुख महत्व है। वे निर्जन में हिमालय पर वास करते हैं। भस्म लपेटे रहते हैं। भूतों और गणों के भी स्वामी कहे जाते हैं-वही लोग जो समाज द्वारा तिरस्कृत हैं, उन्हें शिव अपनाते हैं। वह वैरागी है, औघड़ है, मलंग हैं। वे सुर-असुर सबके देवता हैं। सबके प्रिय। उनका अभिषेक भी जल से किया जाता है। पूजा में मेवे नहीं बेल पत्र, धतूरा आदि चढ़ाए जाते हैं। इतना सादे, भोले भंडारी और सबसे बढ़कर प्रेम की अद्भुत मिसाल, पराकाष्ठा। सती से ऐसा प्रेम जिसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन अब उन्हीं के नाम पर इस कदर नफ़रत, हिंसा, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है कि कुछ कहते नहीं बनता। कांवड़ यात्रा सदियों से होती आ रही है। पहले इसमें दो तरह के लोग जाते थे,एक वो जो आस्थावान हैं, दूसरे जो घर या समाज से तिरस्कृत, अपमानित, बेरोज़गार। जिन्हें इस बहाने घर-समाज में कुछ सम्मान मिल जाता था। इसलिए इसमें दलित-पिछड़े भी जाते रहे। फिर इसके बाद इसमें ऐसे युवा जुड़े जो कुछ मस्ती, सैरसपाटे या नशे आदि के लिए कांवड़ लाने लगे। लेकिन अब इसमें जो चौथी कैटेगिरी जुड़ी गई है जो बेहद खतरनाक है। ये लोग हैं हिंसक, हुड़दंगी, नफ़रती, सांप्रदायिक लोग। ये आस्थावान नहीं हैं, ये एक नफ़रती गैंग है, जिसके लिए शिव की भक्ति और कांवड़ यात्रा एक मौका है, दूसरे लोगों खासकर मुसलमानों को टार्गेट करने का। सांप्रदायिकता का ज़हर बोने का। इन लोगों को आज राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। या कहें कि ये टोली हिंदुत्ववादी दलों और संगठनों द्वारा ही पोषित और प्रायोजित गैंग है। यह सच है कि आज भी शिव में आस्था रखने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। करोड़ों में। और इन्हीं लाखों लोग कांवड़ लेने जाते हैं। इनसे हमें कोई शिकायत नहीं। दिक्कत पैदा करते हैं यह मुट्ठी भर हुड़दंगी नफ़रती लोग जो आज इस पूरी यात्रा पर हावी हो गए हैं। और अब इन्हीं लोगों की वजह से पूरी कांवड़ यात्रा बदनाम हो गई है। इन लोगों के डर से बहुत से धार्मिक, आस्थावान लोग कांवड़ लाने से भी परहेज करने लगे हैं। इन नफ़रती हुड़दंगियों ने एक तरह से इस पूरी यात्रा पर कब्ज़ा कर लिया है। और इन्हें हिंदुत्व की राजनीति के चलते आरएसएस-बीजेपी और उससे जुड़े संगठन और शासन-प्रशासन का समर्थन मिल रहा है। यानी कहा जाए कि कांवड़ यात्रा का 'राजनीतिक अपहरण' हो गया है तो कुछ गलत न होगा। तभी तो इन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान गुंडागर्दी की खुली छूट होती है। एक दिन जुमे या ईद की नमाज़ अगर सड़क पर हो जाए तो सरकार और प्रशासन को दिक्कत होने लगती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के नाम पर अन्य लोगों के लिए महीना-महीना भर रास्ते रोक दिए जाते हैं। रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन कोई टोकने वाला नहीं है। इसके बाद भी आपने हर बार देखा होगा, कभी कांवड़ अपवित्र करने के नाम पर कभी किसी और बहाने सड़क चलते लोगों को निशाना बनाया जाता है, वाहनों में आग लगा दी जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। अभी कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई है लेकिन हरिद्वार से खबर आ रही है कि गंगा जल खंडित होने के आरोप में एक टैंपो चालक को पिटाई कर दी गई। चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और पिछले साल से एक नया ड्रामा शुरू हुआ है कांवड़ मार्ग के दुकानदारों, होटल-ढाबों और यहां तक रेहड़ी-ठेले वालों को भी अपनी नेमप्लेट लगाने का। यानी यह पहचान सुनिश्चित करने का कि फलां होटल-ढाबे या दुकान का मालिक हिंदू है या मुसलमान। और सिर्फ मालिक ही नहीं यानी किसके नाम पर दुकान रजिस्टर है यही नहीं बल्कि कौन उसे चला रहा है, कौन कारीगर है। सब। दरअसल यह सिर्फ़ नफ़रत नहीं मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की भी साज़िश है। जो केवल कांवड़ या नवरात्र पर ही नहीं अब तो हर समय गांव-मोहल्लों में मुसलमान फेरी वालों का प्रवेश निषेध आदि के बोर्ड लगाकर ऐलानिया तौर पर की जाने लगी है। रोज़ ख़बरें आती हैं कि यहां कश्मीरी शॉल बेचने वाले को पीट दिया गया, वहां लव जिहाद का आरोप लगाकर मुसलमानों को दुकान-मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। कभी किसी ने नहीं कहा कि आपको भोजन चुनने का अधिकार नहीं है। आप क्या खाएं, क्या न खाएं, कहां से खाएं, न खाएं ये आपकी इच्छा है। आपको खाने को क्वालिटी और शुद्धता से मतलब होना चाहिए, उसके शाकाहारी और मांसाहारी होने से मतलब होना चाहिए,कौन उसे बना रहा है, बेच रहा है, इससे आपको क्या मतलब। और अगर मतलब भी है तो आप इसके ज़रिये भेदभाव, छुआछूत और घृणा नहीं फैला सकते। कल आप कहेंगे कि जाति भी लिखिए, क्योंकि आपको दलितों से भी परहेज़ है! आपने कभी किसी शादी-ब्याह, समारोह में जाकर मेज़बान से पूछा है कि आप का हलवाई हिंदू है या मुसलमान। या उसके कारीगर और परोसने वाले यानी वेटर किस धर्म-जाति के है? हल्दीराम, बीकानेर या अग्रवाल साहब की मिठाई की दुकान पर जाकर पूछा है कि आपके ये लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले बनाने वाला कारीगर कौन है, हिंदू या मुसलमान। या ये जो डिब्बा बंद मिठाइयां, नमकीन, ब्रेड, चॉकलेट आ रहे हैं उन्हें कहां कौन बनाता है, कौन पैक करता है, कौन डिलीवर करता है। यह पूछा है, नहीं क्यों!, क्योंकि हमें सामान की गुणवत्ता से मतलब होता है, उसके मालिक या कारीगर से नहीं। और मैं पूछता हूं इन नफ़रती और शुद्धतावादी लोगों से वो कैसे तय करेंगे कि सड़क किनारे ठेले पर बिक रहे आम-केले हिंदू के बाग से आए हैं या मुसलमान के। लेकिन उन्हें इसे बेचने वाले से दिक्कत है। और इस तरह बेचने वाले के धर्म से आम-केला-अमरूद भी हिंदू-मुसलमान हो गए। लेकिन इन नफ़रती लोगों को समझाने या रोकने की बजाय, पुलिस-प्रशासन इनकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करता है और शासकीय आदेश जारी करता है कि नाम लिखा जाए। हैलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करता है। इसी वजह से इनके हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड ने जब पिछले बार 2024 में ऐसे बेतुके फरमान जारी किए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए साफ़ आदेश दिया कि दुकानदार को सिर्फ यह दिखाना चाहिए कि वह शाकाहारी या मांसाहारी भोजन बेच रहा है; नाम-पता बताना आवश्यक नहीं। संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार भी यह व्यक्ति की निजता और गरिमा के अधिकार का भी उल्लंघन है। लेकिन इस बार यह फिर शुरू हो गया है। योगी सरकार ने फिर इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। और इस सबसे शह पाकर यह नफ़रती गैंग अब तो एक कदम और आगे बढ़ गया है। अब इन लोगों को केवल नाम से तसल्ली नहीं है, आधार देखकर तसल्ली नहीं है, अब तो वे पैंट खोलकर देख रहे हैं कि फलां आदमी हिंदू है या मुसलमान। अभी उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में ऐसी ही घटना हुई। 28 जून को दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर कांवड़ रूट पर किसी यशवीर महाराज की टीम ने दुकानों और ढाबों पर पहचान अभियान चलाया। इस दौरान पंडित जी वैष्णो ढाबा पर एक कर्मचारी से जबरन पैंट उतारने की कोशिश की गई ताकि धर्म की पहचान की जा सके। इसे क्या कहेंगे आप। आस्था, खाने-पीने में शुद्धता का आग्रह या नफ़रत, सांप्रदायिकता। इस मामले में कार्रवाई के नाम पर अभी तक सिर्फ 6 लोगों को पुलिस ने नोटिस दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एस.टी. हसन ने तो इसे पहलगाम हमले जैसे आतंकी कृत्य बताया है। क्योंकि वहां भी धर्म पूछकर मारा गया था। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य नेताओं ने इसे इसे धार्मिक उत्पीड़न और गैर-कानूनी करार दिया है। यह सब हो रहा है शिव के नाम पर, जो बाह्य आडंबरों से परे, आंतरिक शुद्धता के प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिन्होंने देवता, सुर-असुर किसी में भेदभाव नहीं किया। जिन्होंने समुद्र मंथन से निकला विष खुद पीकर संसार को बचाया लेकिन यह लोग उन्हीं के नाम पर पूरे देश-समाज में नफ़रत का ज़हर फैला रहे हैं। अंत में एक अपील सबसे खासकर आस्थावान कांवड़ियों से कि इस तरह की नफ़रत और गुंडागर्दी का आगे आकर खुलकर विरोध कीजिए, वरना ये आपके धर्म और आस्था को जिस तरह बदनाम कर रहे हैं कल कांवड़ लाने या उठाने में आपको या आपके बच्चों को गर्व, श्रद्धा या शांति महसूस नहीं होगी बल्कि शर्म आएगी।

स्पेस में प्राइवेट सैक्टर की पॉवर

एक्सिओम-4 मिशन यानी एएक्स-4 एक कमर्शियल स्पेस मिशन है जिसे अमेरिका की प्राइवेट कंपनी एक्सिओम स्पेस चला रही है। एक्सिओम-4 मिशन में शुभांशु शुक्ला की सीट के लिए इसरो ने करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि यह रकम पहली नजर में भारी लग सकती है लेकिन देखा जाए तो ये निवेश है। आने वाले समय में यही निवेश भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान और मानव मिशन की दिशा में नई ऊंचाई देगा। यह ट्रेनिंग, रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में बड़ा कदम है। शुभांशु शुक्ला न केवल मिशन के पायलट हैं, बल्कि 14 दिन तक आईएसएस में रहकर विज्ञान से जुड़े 60 प्रयोगों में हिस्सा भी लेंगे। इन प्रयोगों में 7 भारत के इसरो द्वारा डिजाइन किए गए हैं। इनमें माइक्रोएल्गी को स्पेस में उगाने, स्पेस में मसल लॉस का अध्ययन, बीजों के विकास, कंप्यूटर स्क्रीन के प्रभाव और टार्डिग्रेड जैसे जीवों की स्पेस में ताकत की जांच शामिल है। इन एक्सपेरिमेंट्स से भविष्य में स्पेस में खेती करने, लंबे अंतरिक्ष मिशनों के दौरान मानव शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने और स्पेस मिशनों में जीवन सपोर्ट के नए तरीके खोजने में मदद मिलेगी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 286 दिनों की अनिश्चितता और 4,576 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद आखिरकार फ्लोरिडा तट के पास सुरक्षित लैंड कर गए। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स के कैप्सूल में वापस लौटे, जबकि उन्होंने अपनी यात्रा बोइंग के नए स्टार लाइनर यान से शुरू की थी। इस मिशन ने एक बार फिर अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को दर्शाया है। यह गगनयान जैसे भारतीय मानव मिशनों की तैयारी में भी मददगार साबित होगा। अंतरिक्ष में अब सरकारों के नहीं, बल्कि निजी कंपनियों के अंतरिक्ष स्टेशन बनने जा रहे हैं। एक्सिओम-4 मिशन के साथ इस दौड़ ने नई रफ्तार पकड़ ली है।

एक्सिओम स्पेस के अलावा ब्लू ओरिजिन, वोयेगर स्पेस, नॉर्थरप ग्रुमैन और वास्ट जैसी बड़ी कंपनियां ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की होड़ में हैं, जहां भविष्य में आम लोग भी कुछ लाख डॉलर खर्च कर शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव ले सकेंगे। न केवल अंतरिक्ष पर्यटन, बल्कि चिकित्सा अनुसंधान, उच्च तकनीकी निर्माण और फिल्म शूटिंग के लिए भी ये स्टेशन बड़े केंद्र बनेंगे। 2030 तक सेवानिवृत्त होगा आईएसएस। वर्ष 2030 के बाद जब अन्तर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) सेवानिवृत्त होगा, तब ये निजी स्टेशन अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति का नया अध्याय शुरू करेंगे। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र निजी कंपनियों की बढ़ती भागीदारी के साथ बदलाव के दौर में है। इसरो ने उपग्रह लॉन्चर निर्माण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपकर पुन- प्रयोज्य रॉकेट और कक्षीय सुरक्षा जैसी तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह स्काईरूट, अग्निकुल और पिक्सल जैसे स्टार्टअप्स के प्रयासों को मजबूती देता है। वैश्विक अंतरिक्ष हब बनने की राह में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का तालमेल बेहद अहम है। वर्ष 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना एक ऐतिहासिक बदलाव था जिससे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ गई। इसरो और गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर इन-स्पेस ने उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को काफी हद तक बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिये एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस वर्ष 2022 में सबऑर्बिटल रॉकेट, विक्रम-एस लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई। भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जिसमें अग्निकुल कॉसमॉस और ध्रुव स्पेस जैसे स्टार्टअप प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी, उपग्रह निर्माण और अंतरिक्ष सेवाओं में अग्रणी हैं। सिर्फ वर्ष 2021 में ही भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स ने 68 मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 196 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना के निर्माण के लिये इसरो और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, गोदरेज एयरोस्पेस और एल एंड टी जैसी उद्योग की दिग्गज कंपनियों के बीच साझेदारी के माध्यम से सार्वजनिक-निजी सहयोग को और बढ़ावा मिला है। ये कंपनियां प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष यान और उपग्रह उप-प्रणालियों के लिये घटकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आज हमारे पास अंतरिक्ष अवशेष प्रबंधन, नैनो उपग्रह, प्रक्षेपण यान, ग्राउंड सिस्टम, अनुसंधान जैसे नवीनतम क्षेत्रों में काम करने वाले 250 स्टार्टअप मौजूद हैं। पिछले साल से अब तक भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग और भारत के पहले सौर मिशन आदित्य-एल1 के सफल प्रक्षेपण के साथ नई ऊंचाइयों को छुआ। भारत का लक्ष्य अब 2035 तक 'भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन' स्थापित करने और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का है। निसंदेह, अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से देश को बड़ा फायदा होगा। असल में इसरो के मुताबिक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का मूल्य करीब तीन सौ साठ अरब डॉलर है लेकिन भारत की इसमें सिर्फ दो प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसरो का अनुमान है कि देश 2030 तक इस हिस्सेदारी को बढ़ा कर नौ प्रतिशत तक ले जा सकता है।

मुनीर की डिप्लोमेसी हुई ध्वस्त

पिछले हफ्ते भारत में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान और चीन की साजिश को नाकाम करते हुए संगठन के संयुक्त वक्तव्य को जारी नहीं होने दिया था। जब रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उस संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिसमें पहलगाम हमले का उल्लेख तक नहीं था, बल्कि पाकिस्तान में हुए बलूचिस्तान हमले का जिक्र था। इस घटना के एक सप्ताह बाद अमेरिका में क्वाड देशों अमेरिका, आस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। अमेरिका की धरती से जारी हुए बयान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान भारत की ताकत को समझने की भूल कर लगातार आतंकवादी साजिशें रच देता है। उसने बालाकोट एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से कोई सबक नहीं सीखा। इस बार उसने पहलगाम में हमला करवाकर खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। भारत ने इस हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर से डरे बैठे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असिम मुनीर तो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया और डोनाल्ड ट्रम्प के घर लंच डिप्लोमेसी भी कर आए। मगर अब विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने एक ही झटके में मुनीर की डिप्लोमेसी को ध्वस्त कर दिया। यद्यपि क्वाड के संयुक्त वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम नहीं दिया गया लेकिन वक्तव्य का पाकिस्तान के लिए कड़ा और स्पष्ट संदेश है। क्वाड ने पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कठघरे में लाने की हुंकार भरी। असिम मुनीर को लगा था कि अमेरिका उसका माईबाप हो गया है और वह भारत का साथ नहीं देगा। मगर जयशंकर की मौजूदगी ने उसका सारा गेम पलट दिया। जहां तक वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम नहीं लिए जाने का सवाल है, उसके पीछे अमेरिका की दोगली चालें है। 2018 में अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने खास अंदाज में रावलपिंडी और इस्लामाबाद द्वारा वाशिंगटन का फायदा उठाने की भावना को स्पष्ट किया था, अमेरिका ने पिछले 15 वर्षों में पाकिस्तान को मूर्खतापूर्ण तरीके से 33 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता दी है और उन्होंने हमारे नेताओं को मूर्ख समझते हुए हमें झूठ और धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया है,वे आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देते हैं।'' कुछ दिन पहले उन्होंने कहा-मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं।'' ट्रम्प और जनरल आसिम मुनीर के बीच व्हाइट हाउस में अभूतपूर्व लंच मीटिंग को पहली बार पाकिस्तान में राष्ट्राध्यक्ष न होने वाले किसी सैन्य नेता को यह सम्मान दिया गया है- एक बड़े यू-टर्न के रूप में देखना सरल होगा। वास्तव में, पिछले तीन दशकों में भारत-अमेरिका संबंध आर्थिक और सामरिक हितों और साझा मूल्यों के अभिसरण के आधार पर लगातार गहरे हो रहे हैं, भले ही अमेरिका-पाकिस्तान संबंध अधिक अस्थिर हो गए हों। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वर्तमान क्षण परिवर्तनशील है और दिल्ली को सावधानी से चलना चाहिए। क्वाड समूह ने पाकिस्तान के साथ-साथ पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर उसे सख्त चेतावनी दी है।

सम्पादकीय...

दिल्ली की सत्ता में बदलाव की दस्तावेज़ी कहानी

रेखा गुप्ता का सियासी सफर एक राजनीतिक यात्रा का ऐसा लेखबद्ध दस्तावेज़ है जो महज घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि उन घटनाओं के पीछे की मानसिकता, रणनीति और नेतृत्व दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। यह पुस्तक भारत की राजधानी दिल्ली के 2025 के ऐतिहासिक चुनावों के बहाने भारतीय लोकतंत्र के चरित्र, मतदाता की परिपक्वता और नेतृत्व परिवर्तन की जटिल प्रक्रियाओं की पड़ताल करती है। लेखक गोपाल शर्मा, जिन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में वर्षों तक अपना योगदान दिया है, इस राजनीतिक यात्रा को एक अनुभवी साहित्यकार और गहन शोधकर्ता की दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक को 15 अध्यायों में बांटा गया है, जिनमें हर अध्याय एक नए मोड़, नए दृष्टिकोण और नई राजनीतिक अनुभूति का वाहक है। पुस्तक की प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक, यह पाठक को उस परिवर्तनशील राजनीति के बीच ले जाती है, जहां नेता बनते हैं, मिटते हैं और फिर नई नेतृत्व-धारा उभरती है। शपथ ग्रहण समारोह से शुरुआत कर पुस्तक एक दमदार राजनीतिक आरंभ का आभास कराती है। बिखरते केंद्र की अबूझ कहानी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जैसे अध्याय गहन विश्लेषण और अंदरूनी राजनीति की बारीकियों से भरपूर है। बात उस रात की ! और गूंजे विजय शंखनाद ! जैसे अध्यायों में भावनात्मक और नाटकीय तत्वों की झलक भी मिलती है। आरती यमुना मैया की ! और दिल्ली की सत्ता का नया चेहरा जैसे अध्याय प्रतीकात्मक राजनीति और सांस्कृतिक संदर्भों को जोड़ते हैं। राजनीति में नारी उत्कर्ष की नई इबारत विशेष रूप से प्रेरक अध्याय है, जो महिला नेतृत्व की महत्ता को रेखांकित करता है। रेखा गुप्ता तक की मेरी यात्रा, लेखक की व्यक्तिगत भागीदारी और शोध यात्रा की आत्मीय झलक देता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह लेखन केवल एक विश्लेषण नहीं, बल्कि आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया भी है। यह पुस्तक केवल एक राजनेता की जीवनी नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में उभरते सामाजिक बदलावों, नेतृत्व के बदलते मानकों और मतदाता की जागरूकता की कथा है। रेखा गुप्ता का छात्रसंघ राजनीति से मुख्यमंत्री पद तक का सफर प्रेरणादायक तो है ही, साथ ही यह सत्ता तक पहुंचने की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती भी देता है। लेखक बड़ी कुशलता से अरविंद केजरीवाल के पतन और भाजपा की रणनीतिक विजय को नाटकीयता से बचाकर यथार्थपरक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक चेतना पुस्तक के हर पृष्ठ पर स्पष्ट झलकती है। गोपाल शर्मा की भाषा गम्भीर, विद्वतापूर्ण किंतु सहज है। राजनीतिक विमर्श को भी उन्होंने साहित्यिक गरिमा और गहराई के साथ प्रस्तुत किया है। उन्होंने ज़मीनी राजनीति और उच्च स्तरीय नेतृत्व के बीच की दूरी को शब्दों से पाटने का साहसिक प्रयास किया है। कहीं-कहीं पर पाठक को लगेगा कि लेखन में अत्यधिक विश्लेषणात्मक प्रकृति है, लेकिन वह लेखक की अकादमिक पृष्ठभूमि को देखते हुए स्वाभाविक प्रतीत होती है। गोपाल शर्मा की विद्वता का प्रमाण उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां, चार दशकों का शिक्षण अनुभव, और 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन है। उनके लेखन में राजनेताओं, समाज सुधारकों और साहित्यकारों के जीवन और विचारों की गहन पड़ताल मिलती है। चाहे वह नेल्सन मंडेला, कमला हैरिस, ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राम नाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू जैसी प्रभावशाली शख्सियतों की जीवनियाँ हों या फिर जाक देरिदा और मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यिक दिग्गजों पर उनके आलोचनात्मक अध्ययन – हर पंक्ति में शोध और समझ की गहराई स्पष्ट झलकती है। यह पुस्तक भी उन्हीं की समर्पित शोधशीलता, साहित्यिक समझ और राजनीतिक दृष्टि का प्रमाण है। उन्होंने न केवल रेखा गुप्ता को एक राजनेता के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि उन्हें एक प्रतीकात्मक महिला नेतृत्व के रूप में गढ़ा है। वर्तमान भारत में जहाँ राजनीति अब केवल नीतियों का नहीं, छवियों का खेल बनती जा रही है, वहाँ यह पुस्तक एक ज़रूरी हस्तक्षेप है। यह हमें बताती है कि चुनाव जीतना केवल नारा और प्रचार नहीं, बल्कि भरोसे, संघर्ष और रणनीति का परिणाम है। 2025 के दिल्ली चुनावों को जिस दृष्टिकोण से पुस्तक में चित्रित किया गया है, वह पत्रकारिता के तात्कालिक विश्लेषणों से कहीं आगे जाकर इतिहास का हिस्सा बन जाता है। यह पुस्तक लोकतंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया को एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करती है। रेखा गुप्ता की जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व की नयी इबारत है। लेखक ने इस बात को बहुत ही संजीदगी और शक्ति के साथ रेखांकित किया है कि किस तरह एक महिला ने संघर्षों की राह से होते हुए नेतृत्व की ऊँचाइयों को छुआ। दिल्ली 2025– रेखा गुप्ता का सियासी सफर एक अत्यंत पठनीय, शोधपरक और प्रेरणादायक पुस्तक है, जो राजनीति के केवल बाह्य स्वरूप को नहीं, बल्कि उसके भीतरी ताने-बाने को उजागर करती है। यह पुस्तक राजनीतिक शौकीनों, पत्रकारिता के विद्यार्थियों, प्रशासनिक तैयारी कर रहे युवाओं और समकालीन इतिहास में रुचि रखने वाले हर पाठक के लिए आवश्यक है। यह पुस्तक न केवल रेखा गुप्ता के नेतृत्व की कहानी है, बल्कि उस भारत की भी कहानी है, जो अब नए नेतृत्व, नए दृष्टिकोण और नई राजनीति की ओर अग्रसर है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैंथालियन एक्स, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN2001/0882)

गुजरात से बड़ी कार्रवाई, हथकड़ी लगा 250 अवैध बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट

अहमदाबाद। एक बड़ी कार्रवाई में 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गुजरात से ढाका भेजा गया। वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से यह निर्वासन किया गया। ऑपरेशन को सुरक्षित तरीके से अंजाम देने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए थे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी बांग्लादेशी नागरिकों के हाथ हथकड़ी से बांध दिए गए थे। उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों से बसों में पुलिस सुरक्षा के तहत हवाई अड्डे तक लाया गया। यह कार्रवाई गुजरात में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी अप्रवासियों के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। पिछले दो महीनों में, राज्य में अवैध रूप से रह रहे 1,200 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है और उन्हें निर्वासित किया गया है। राज्य सरकार, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय में, सभी अनधिकृत विदेशी नागरिकों को निकालने के प्रयासों को तेज कर रही है। यह अभियान अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट सहित प्रमुख शहरी केंद्रों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहा है। इन शहरों में अवैध प्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसके कारण पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने निगरानी और सत्यापन को बढ़ा दिया है। अभियान के हिस्से के रूप में, अधिकारी नकली पहचान पत्रों का उपयोग करके भारत में रहने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए गहन दस्तावेज़ जाँच कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए कई व्यक्तियों के पास जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेज पाए गए।

मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं, थप्पड़ कांड पर सीएम फडणवीस का साफ संदेश, किया सख्त कानूनी कार्रवाई का वादा

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के सदस्यों द्वारा ठाणे में एक दुकानदार पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना को भाषा के नाम पर गुंडागर्दी का मामला बताया और सख्त कानूनी कार्रवाई का वादा किया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर गर्व करना गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई भाषा के कारण गुंडागर्दी करता है, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भाषा के आधार पर लोगों की पिटाई करता है, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फडणवीस ने पुष्टि की कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की है तथा ऐसी घटनाएं दोबारा होने पर सख्त परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी मराठी पर गर्व है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस तरह से अन्याय नहीं किया जा सकता, यह हमें ध्यान में रखना होगा। और कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी पर विवाद पैदा करते हैं। यह कैसी सोच है और यह कैसी हरकत है? इसलिए, कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह घटना 1 जुलाई को एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रकाश में आई, जिसमें एमएनएस कार्यकर्ताओं को एक मिठाई की दुकान के मालिक से भिड़ते और उस पर हमला करते हुए दिखाया गया, क्योंकि उसने कथित तौर पर मराठी में बात करने से इनकार कर दिया था। परेशान करने वाले फुटेज में तीन लोग दुकान में घुसते और दुकानदार से उसकी भाषा पसंद के बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उससे पूछा गया कि वह मराठी क्यों नहीं बोल रहा है, तो दुकानदार ने शांति से जवाब दिया मुझे नहीं पता था कि मराठी बोलना अनिवार्य है। किसी को मुझे सिखाना होगा। फिर उनमें से एक आदमी ने उसे चेतावनी दी, मार खाएगा? जिसके बाद उसने हिंसक हमला किया। हमलावरों ने दुकानदार को कई बार थप्पड़ मारे, गाली-गलौज की और उसका कारोबार बंद करने की धमकी दी। जब दुकानदार ने जवाब दिया कि महाराष्ट्र में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमलावरों का गुस्सा और भड़क गया।

आगामी बिहार विधानसभा सत्र एनडीए का आखिरी सत्र होगा, कांग्रेस बोली- 'इंडिया गठबंधन की सत्ता में वापसी तय

नई दिल्ली। कांग्रेस की महिला इकाई ने शुक्रवार को दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा सत्र सत्तारूढ़ राजग का आखिरी सत्र होगा, क्योंकि इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव के बाद 'इंडिया गठबंधन' का सत्ता में वापस आना तय है। यह बात अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने कही, जिन्होंने राज्य की राजधानी पहुंचने पर यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत की। लांबा ने कहा, ''राजग अपने आखिरी विधानसभा सत्र का सामना करने जा रहा है (सत्तारूढ़ गठबंधन के रूप में)। 'इंडिया गठबंधन' की बिहार में सत्ता में वापसी तय है। राज्य में विधानमंडल का मानसून सत्र 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच निर्धारित है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। लांबा ने कहा, ''सरकार कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर बुरी तरह विफल रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में इसका 'ट्रैक रिकॉर्ड' खास तौर पर निराशाजनक रहा है। हम सभी को हाल ही में एक नाबालिग दलित लड़की पर हुए यौन हमले की घटना याद है, जिसने कुछ दिन बाद चिकित्सा सहायता के अभाव में दम तोड़ दिया।

मल्लिकार्जुन खरगे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला सरकार की गलत विदेश नीति के कारण बढ़ रहे दुश्मन,

हैदराबाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को गलत बताते हुए कहा कि इसकी वजह से भारत के चारों ओर दुश्मन बनते जा रहे हैं। हैदराबाद में आयोजित सामाजिक न्याय समर भेरी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरगे ने कहा कि पीएम मोदी अब तक 42 देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन मणिपुर नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं। उन्होंने कहा, उनकी विदेश नीति ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ दुश्मन बन गए हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। अब नेपाल भी हमसे दूर होता जा रहा है। सभी देश हमसे दूरी बना रहे हैं। खरगे ने यह भी आरोप

लगाया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी है और संविधान को कमजोर कर दिया है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर तंज कसते हुए खरगे ने कहा, अगर कोई मोदी को टोपी या मेडल दे दे, तो वे उसे पहनकर घूमते रहते हैं। लेकिन उन्हें देश के किसानों और आम जनता की चिंता नहीं है। इसके साथ ही खरगे ने सवाल उठाया, कि मोदी जी, आप कहां हैं? आप आठ देशों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की ओर नहीं देख रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के इस जुबानी हमले से देश की राजनीति जरूर गर्माएगी। दरअसल, कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इस बीच दो बार सर्वदलीय बैठक जरूर हुई लेकिन पीएम मोदी इन बैठकों में नहीं शामिल हुए। जिसके बाद से कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला तेज हो गया है।

अमित शाह ने श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का किया अनावरण

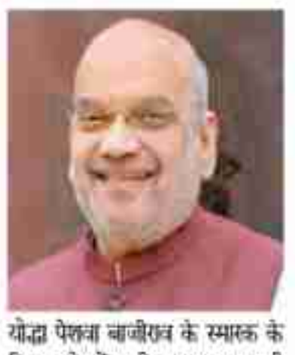

पुणे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को महाराष्ट्र दौरे पर हैं। वे गुरुवार रात को पुणे पहुंचे थे। यहां शाह चार कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सबसे पहले उन्होंने पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा की प्रतिमा का अनावरण किया। 13.5 फुट ऊंची, 4,000 किलोग्राम वजन की कांस्य प्रतिमा श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवा प्रतिष्ठान की ओर से एनडीए को दान की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), खड़कवासला के प्रशिक्षुओं से बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मराठा साम्राज्य के

योद्धा पेशवा बाजीराव के स्मारक के लिए पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) परिसर सबसे उपयुक्त स्थान है। शाह ने एनडीए परिसर में प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि एनडीए उनके स्मारक के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि यह वह अकादमी है, जहां सैन्य नेतृत्व को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगर शिवाजी महाराज की ओर से शुरू की गई और पेशवाओं की ओर से 100 वर्षों तक आगे बढ़ाई गई स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी गई होती, तो भारत का मूल ढांचा अस्तित्व में नहीं होता। अपने 40 वर्षों के जीवन में पेशवा बाजीराव ने एक अमर इतिहास लिखा, जिसे कोई अन्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल समेत अन्य लोग इस समारोह में शामिल हुए।

वाशिम में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे से दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। जहां पर गुरुवार रात एक कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी शुक्रवार को स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने दी। हादसा वनोजा और करंजा के बीच हुआ, जब कार चालक नियंत्रण खो बैठा। मंगरूलपीर पुलिस के अनुसार, नागपुर जिले के उमरेड निवासी एक परिवार के पांच सदस्य पुणे में आयोजित एक समारोह में शामिल होने के बाद कार से लौट रहे थे। घटना स्थल के करीब, चैनल नंबर 215 के पास कार चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार डिवाइडर से टकरा गई।

चुनाव आयोग का दावा- बिहार में 1.5 करोड़ घरों में पहुंचे बीएलओ, 87 फीसदी मतदाताओं को मिले नामांकन फॉर्म

नई दिल्ली।

बिहार में 1.5 करोड़ घरों में बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) की पहली यात्रा आज पूरी हो गई है और राज्य में चल रहे विशेष तीव्र पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत अब तक कुल 7,89,69,844 यानी लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 87 प्रतिशत से अधिक नामांकन फॉर्म (यानी 6,86,17,932 फॉर्म) वितरित किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है। आयोग ने बताया कि बाकी घर या तो बंद थे या उनमें मृत मतदाता रहते थे या वे प्रवासी हो सकते हैं या यात्रा पर गए होंगे। चूंकि, बीएलओ तीन बार घरों पर जाएंगे, इसलिए यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। चुनाव आयोग ने बताया कि आंशिक रूप से भरे हुए फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट और ECINET ऐप पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है और मतदाता स्वयं ECINET ऐप के जरिए भरे हुए फॉर्म अपलोड कर सकते हैं।

एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग कर रहे बीएलए

इसके अलावा, विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त किए गए 1,54,977 बूथ स्तर एजेंट (बीएलए) भी एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। दो जुलाई तक भाजपा ने 52,689 बीएलए नियुक्त किए हैं। इसके बाद राजद ने 47,504; जेडीयू ने

34,669; कांग्रेस ने 16,500; राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 1913, भाकपा माले (लिबरेशन) ने 1271, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 1153, माकपा ने 578, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 270 बीएलए नियुक्त किए हैं। इसके अलावा, बसपा (74), एनपीपी (3) और आम आदमी पार्टी (1) ने भी अपने एजेंट तैनात किए हैं। हर बीएलए एक दिन में अधिकतम 50 प्रमाणित फॉर्म जमा कर सकता है।

बीएलओ प्राप्त कर चुके 38 लाख भरे हुए फॉर्म

चुनाव आयोग ने बताया, अब तक करीब पांच फीसदी भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म यानी करीब 38 लाख फॉर्म बीएलओ प्राप्त कर जा चुके हैं, जो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

उनका एकमात्र उद्देश्य पहले समावेश है, जिसे आयोग बार-बार दोहराता रहा है। एसआईआर के अनुसार, किसी भी मतदाता का नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि प्री-प्रिंटेड नामांकन फॉर्म को 25 जुलाई 2025 से पहले हस्ताक्षर करके जमा किया जाए। साथ ही, अपलोड किए गए फॉर्म का सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। कुछ जगहों से संदेह जताए जाने के बावजूद आयोग का मानना है कि एसआईआर के जरिए सभी पात्र लोगों का नाम शामिल किया जाएगा।

एक बॉर्डर, तीन दुश्मन- उप सेना प्रमुख

ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान को चीन की पूरी मदद मिली, अगली बार तैयार रहना होगा- आर्मी

नई दिल्ली।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को हर संभव सहायता प्रदान की थी. उपसेना प्रमुख ने चीन-पाकिस्तान के नेक्सस का खुलासा किया.पाकिस्तान चीनी हथियारों की प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा था.चीन ने अपने हथियारों का परीक्षण करने के लिए पाकिस्तान को एक लाइव लैब बनाया.तुर्की ने भी संघर्ष में महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया. भारत को और अधिक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा था. उपसेना प्रमुख (क्षमता विकास एवं निर्वाह) लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने चीन-पाकिस्तान के इस नापाक नेक्सस के बेनकाब किया है. उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की हर

संभव मदद की थी. उनके मुताबिक इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान चीनी हथियारों की प्रयोगशाल बना हुआ था. फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में बोलते हुए, उप सेना प्रमुख ने कहा, एयर डिफेंस और पूरे ऑपरेशन के दौरान इसे कैसे अंजाम दिया गया, यह महत्वपूर्ण था. इस बार, हमारे जनसंख्या केंद्रों पर ध्यान (पाक द्वारा हमला) नहीं दिया गया, लेकिन अगली बार, हमें इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा, हमारे पास एक बॉर्डर था लेकिन दो प्रतिद्वंद्वी थे, वास्तव में तीन थे. पाकिस्तान सबसे आगे था. चीन हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था. पाकिस्तान के पास 81 फीसदी सैन्य हार्डवेयर चीनी हैं. उन्होंने कहा, चीन अन्य हथियारों के मुकाबले में अपने हथियारों का

- ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने हमें हथियारों की टेस्टिंग लैब समझा
- तुर्किये ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए

परीक्षण करने में सक्षम था, इसलिए यह उनके लिए एक लाइव लैब की तरह था. उन्होंने संघर्ष के बीच तीसरे प्रतिद्वंद्वी के रूप में तुर्की की भूमिका की भी बात की. उन्होंने कहा कि तुर्की ने भी उस प्रकार का समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने आगे कहा, जब डीजीएमओ स्तर की वार्ता चल रही थी तब पाकिस्तान के पास चीन से हमारे महत्वपूर्ण वैक्टरों का लाइव अपडेट था. हमें एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर आतंकी ढांचे पर सटीक हमले करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना भी की. उन्होंने लक्ष्य के चयन और योजना में रणनीतिक संदेश, टेक्नोलॉजी और मानव बुद्धि के एकीकरण पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा, ...ऑपरेशन सिन्दूर से कुछ सबक हैं. नेतृत्व द्वारा रणनीतिक संदेश स्पष्ट था... जिस तरह से हमने कुछ साल पहले किया था, उस तरह से दर्द को अवशोषित करने की कोई गुंजाइश नहीं है... लक्ष्यों की योजना और उनका चयन टेक्नोलॉजी और मानव बुद्धि का उपयोग करके जमा किए गए बहुत सारे डेटा पर आधारित था. इसलिए कुल 21 लक्ष्यों की पहचान की गई, जिनमें से नौ लक्ष्यों पर हमने सोचा कि हमला करना समझदारी होगी... यह केवल अंतिम दिन या अंतिम घंटे में निर्णय लिया गया था कि इन नौ लक्ष्यों पर हमला किया जाएगा.

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: हिंदू पक्ष को झटका

हाईकोर्ट ने ईदगाह को 'विवादित ढांचा' मानने से किया इनकार

प्रयागराज।

मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित परिसर मानने से इनकार कर दिया है. यह फैसला जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया. कोर्ट ने कहा कि मौजूद तथ्यों और याचिका के आधार पर ईदगाह को फिलहाल विवादित ढांचा घोषित नहीं किया जा सकता. हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि ईदगाह का निर्माण श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया. हिंदू पक्ष के पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में 5 मार्च 2025 को मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किए जाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इस पर 23 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने मासिर ए आलम गिरी से लेकर मथुरा के कलेक्टर रहे एफएस ग्राउस तक के समय में लिखी गई इतिहास की पुस्तकों का हवाला देते हुए कोर्ट के समक्ष कहा था कि वहां पहले मंदिर था, वहां पर मस्जिद होने का कोई साक्ष्य आज तक शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष न्यायालय में पेश नहीं कर सका. साथ ही न खसरा खतौनी में मस्जिद का नाम है और न ही नगर निगम में उसका कोई रिकॉर्ड है. न कोई टैक्स दिया जा रहा. उनका दावा है कि शाही ईदगाह प्रबंध कमेटी के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट भी हो चुकी है, फिर इसे मस्जिद क्यों कहा जाए ऐसे में मस्जिद विवादित ढांचा घोषित हो.

क्या बीजेपी को मिलेगी पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष? इन नामों को लेकर चर्चा तेज

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल हो रहा है। छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय इकाइयों के लिए पार्टी प्रमुखों की नियुक्ति के बाद, बीजेपी अब अपना ध्यान राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने पर केंद्रित कर रही है। जेपी नड्डा 2020 से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं। उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा था, लेकिन भाजपा ने इसे 2024 तक बढ़ा दिया ताकि वह लोकसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व कर सकें।

हालांकि इस बात पर सस्पेंस बना हुआ है कि प्रमुख पद कौन संभालेगा, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि पार्टी को पहली बार महिला अध्यक्ष मिल सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व्यापक विचार-विमर्श कर रहे हैं और शीर्ष पद के लिए कई प्रमुख महिला राजनेताओं पर विचार किया जा रहा है, जिनमें निर्मला सीतारमण, डी पुरंदेश्वरी और वनाथी श्रीनिवासन जैसी नेता शीर्ष दावेदार हैं। प्रमुख दावेदारों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी के भीतर उनके नाम ने काफी लोकप्रियता हासिल की है, अंदरूनी सूत्रों ने उनके व्यापक मंत्री

पद के अनुभव और संगठनात्मक गहराई का हवाला दिया है। अगर सीतारमण को चुना जाता है, तो वह न केवल भाजपा की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी, बल्कि पार्टी को दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में भी मदद करेंगी। उनकी पदोन्नति लोकसभा में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता का संकेत देगी - जो अगले परिसीमन अभ्यास के बाद लागू होने की उम्मीद है। भाजपा के भीतर एक अनुभवी नेता, सीतारमण पहले रक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में पार्टी के सबसे हाई-प्रोफाइल चेहरों में से एक हैं। गंभीर विचार में एक और नाम है डी पुरंदेश्वरी का, जो भाजपा की आंध्र प्रदेश की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। अपनी बहुभाषी दक्षता और विभिन्न दलों के राजनीतिक अनुभव के लिए जानी जाने वाली, वह क्षेत्रीय अपील और राष्ट्रीय दृश्यता का एक अनूठा मिश्रण लेकर आती हैं। तमिलनाडु की वकील से राजनेता बनी श्रीनिवासन भी कथित तौर पर मैदान में हैं।

वर्तमान में कोयंबटूर दक्षिण से विधायक के रूप में कार्यरत, वह 1993 से भाजपा के साथ हैं और लगातार रैंकों में ऊपर उठती रही हैं। उनकी पिछली भूमिकाओं में राज्य सचिव, महासचिव और पार्टी की तमिलनाडु इकाई के उपाध्यक्ष शामिल हैं।

ट्रंप का बिग ब्यूटीफल बिल अब कानून बनने को तैयार

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का बजट विधेयक प्रतिनिधि सभा में अंतिम मतदान के बाद कानून बनने के लिए तैयार है। अब राष्ट्रपति आज यानी शुक्रवार को एक समारोह के दौरान इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप प्रशासन के लिए इस विधेयक को पारित करना आसान नहीं रहा है। इस विधेयक के कारण सामाजिक कार्यक्रमों और व्यय के स्तर को लेकर ट्रम्प की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों से भी ठन गई है, जो कांग्रेस के दोनों सदनों को नियंत्रित करते हैं।

अमेरिका का संघीय घाटा 10 वर्षों में 3.3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ सकता है

कांग्रेस के बजट कार्यालय का अनुमान है कि इस विधेयक के कारण अगले 10 वर्षों में संघीय घाटे में 3.3 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है। इस बिल के कानून बनने से लाखों लोग स्वास्थ्य बीमा से वंचित हो सकते हैं। हालांकि इन पूर्वानुमानों को व्हाइट हाउस सिरे से खारिज करता रहा है।

इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी सीनेट में मतदान के दौरान, उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस को विधेयक पारित करने के लिए टाई-ब्रेकिंग वोट डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। सदन में वोटिंग के दौरान विधेयक की संभावनाओं को लेकर सांसद अनिश्चित दिखे। हालांकि गुरुवार को घंटों की बहस के बाद रिपब्लिकन पार्टी के विद्रोही आखिरकार इसके पक्ष में आ गए।

1. 2017 की ट्रम्प की कर कटौती का विस्तार

अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रम्प ने कर कटौती और रोजगार अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अधिकांश आय वर्गों के निगमों और व्यक्तियों के लिए करों में कमी की गई थी। ट्रम्प ने इस कानून को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला बताया था, लेकिन विशेषज्ञों का तर्क है कि इससे सबसे अधिक लाभ धनी अमेरिकियों को हुआ है। 2017 में लागू कानून के मुख्य प्रावधान दिसंबर में समाप्त होने वाले हैं, नए बिग ब्यूटीफल बिल का उद्देश्य उन कर कटौतियों को स्थायी बनाना है। इस बिल के कानून बनने से 2028 तक आम लोगों के लिए मानक कटौती में 1,000 डॉलर और विवाहित जोड़ों के लिए 2000 डॉलर का इजाफा होगा।

2. मेडिकेड में भारी कटौती और बदलाव

इस बिल के कानून बनने से अमेरिकियों को मिलने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कटौती हो सकती है। इस बिल के जरिए रिपब्लिकंस ने मेडिकेड के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध और आवश्यकताएं जोड़ दी हैं। मेडिकेड एक ऐसा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जिस पर लाखों विकलांग और निम्न आय वाले अमेरिकी निर्भर हैं। मेडिकेड में परिवर्तन- जो संघीय व्यय का सबसे बड़ा घटक है। यह अमेरिका में राजनीतिक विवाद का एक बड़ा कारण रहा है। मेडिकेड में एक बड़े बदलाव के तहत उन निःसंतान वयस्कों के लिए काम की अधिक आवश्यकता तय की गई है, जो बिना

किसी विकलांगता के हैं। बिल के अनुसार, मेडिकेड योग्यता प्राप्त करने के लिए, उन्हें दिसंबर 2026 से प्रति माह कम से कम 80 घंटे काम करना होगा। कार्यक्रम में प्रस्तावित एक और बदलाव यह है कि मेडिकेड के लिए अब साल में एक बार की जगह दो बार यानी हर छह महीने में रीइनरोलमेंट कराना होगा। नामांकन कराने वालों को अतिरिक्त आय और निवास के सत्यापन का भी प्रमाण देना होगा। कांग्रेस के बजट कार्यालय के अनुमानों के मुताबिक प्रस्तावित बदलावों के कारण अगले दशक के अंत तक लगभग 12 मिलियन अमेरिकी अपना स्वास्थ्य कवरेज खो सकते हैं।

3. सामाजिक सुरक्षा कर

चुनाव प्रचार के दौरान ट्रम्प ने सामाजिक सुरक्षा आय पर कर समाप्त करने की शपथ ली थी- जो सेवानिवृत्ति आयु के अमेरिकियों और विकलांग लोगों को मासिक भुगतान है। सदन का विधेयक उस वादे को पूरा करने में विफल रहा, लेकिन इसने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अस्थायी रूप से 4,000 तक की मानक कटौती को बढ़ा दिया। यह कटौती 2025-28 तक लागू रहेगी। सीनेट रिपब्लिकन ने सामाजिक सुरक्षा कर छूट के विस्तार तथा एक वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिसके तहत प्रति वर्ष 75,000 डॉलर से अधिक नहीं कमाने वाले वृद्ध अमेरिकियों को 6,000 डॉलर की कर कटौती प्रदान की जाएगी।

4. राज्य और स्थानीय कर कटौती में वृद्धि (साल्ट)

विधेयक राज्य और स्थानीय करों (साल्ट) के लिए कटौती की सीमा बढ़ाता है।

वर्तमान में करदाताओं के लिए संघीय करों में से कटौती की सीमा 10,000 है। यह सीमा इस वर्ष समाप्त हो रही है।

सीनेट द्वारा स्वीकृत विधेयक के अनुसार यह राशि 10,000 डॉलर से बढ़कर 40,000 डॉलर कर दी गई है - लेकिन पांच वर्ष बाद यह पुनः 10,000 डॉलर हो जाएगी। नमक कर सदन में एक बड़ा मुद्दा था, खासकर कुछ डेमोक्रेटिक नियंत्रित शहरी क्षेत्रों में रिपब्लिकन के समर्थकों के लिए। व्यय विधेयक के सदन के संस्करण में पाँच साल की सीमा शामिल नहीं थी, इसलिए सीनेट के बदलाव सदन के कुछ रिपब्लिकन के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं।

5. खाद्य लाभ में कटौती

पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (स्नैप) में भी सुधार किए गए हैं, जिसका उपयोग 40 मिलियन से अधिक निम्न आय वाले अमेरिकियों द्वारा किया जाता है। सीनेट विधेयक में राज्यों से इस कार्यक्रम में अधिक योगदान देने की अपेक्षा की गई है, जो वर्तमान में पूरी तरह से संघीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सरकार उन राज्यों को लाभ का पूरा वित्तपोषण जारी रखेगी जिनकी भुगतान त्रुटि दर 6% से कम है, लेकिन उच्च त्रुटि दर वाले राज्यों को कार्यक्रम की लागत का 5% से 15% तक देना होगा। यह परिवर्तन 2028 में शुरू होगा।

6. ओवरटाइम पर कोई कर नहीं

बजट विधेयक में «टिप्स या ओवरटाइम पर कोई कर नहीं» का प्रावधान किया गया है। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान इसका वादा किया था। सदन द्वारा विचाराधीन सीनेट विधेयक व्यक्तियों को अपने करों से टिप वेतन और ओवरटाइम की एक निश्चित राशि की कटौती करने की अनुमति देगा। हालांकि, वार्षिक आय के आधार पर उन लाभों को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव बिल में है। व्यक्तियों के लिए 150,000 और संयुक्त फाइलरों के लिए 300,000 से शुरू होता है।

7. स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहन में कमी

सदन और सीनेट रिपब्लिकन के बीच सबसे उल्लेखनीय मतभेदों में से एक सीनेट का स्वच्छ ऊर्जा कर छूट का प्रस्ताव है। यद्यपि दोनों ने बाइडन युग के संघीय स्वच्छ ऊर्जा कर क्रेडिट को समाप्त करने का आह्वान किया, लेकिन सीनेट रिपब्लिकन ने उन्हें धीरे-धीरे समाप्त करने को मंजूरी दी। उदाहरण के लिए, सीनेट ने पवन और सौर ऊर्जा फार्म बनाने वाली कंपनियों के लिए कर क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए रास्ते को आगे बढ़ाया है। हालांकि, सदन और सीनेट दोनों ही संस्करण उन कंपनियों को क्रेडिट देने से इनकार करते हैं जिनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं का संबंध «चिंताजनक विदेशी इकाई» जैसे चीन से हो सकता है। इस साल निर्माण शुरू करने वाली कंपनियां पूर्ण कर छूट के लिए पात्र हो सकती हैं। यदि वे 2026 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 60% हो जाती है और यदि वे 2027 में निर्माण शुरू करती हैं तो यह छूट 20% हो जाती है। 2028 में यह छूट समाप्त हो जाएगी। विधेयक के सदन संस्करण में उन कम्पनियों के लिए कर छूट को लगभग तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। अब चूंकि विधेयक सदन से पारित हो चुका है, अब इसका अगला पड़ाव राष्ट्रपति के पास आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करके कानून का रूप देने के लिए पहुंचना है। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प 4 जुलाई को एक समारोह में इस पर हस्ताक्षर करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया पर एक शब्द के संदेश के साथ बिल के पारित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अमेरिकी झंडे की तस्वीर के साथ कहा, हम जीत गए!

अमेरिका ने चीन को दी राहत, सॉफ्टवेयर निर्यात प्रतिबंध हटाया; व्यापार वार्ता के बाद नरम हुआ रुख

नई दिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को राहत देते हुए चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं। यह कदम हाल ही में लंदन में हुई व्यापार वार्ता के तहत दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए उठाया गया है। सभी तीन प्रमुख चिप डिजाइन सॉफ्टवेयर कंपनियों- सिनोप्सिस, कैडेंस और सीमेंस ने बताया कि उन्हें अमेरिकी वाणिज्य विभाग से मई में लगाए गए प्रतिबंधों के हटाए जाने की सूचना दी गई है। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार, तीनों कंपनियां चीन के इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन बाजार के 70 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करती हैं। मई में जब बीजिंग ने दुर्लभ धातुओं के निर्यात को सीमित करने का फैसला लिया था ,तब अमेरिका ने प्रतिशोध में चिप डिजाइनिंग टूल्स की बिक्री पर रोक लगाई थी। इसके बाद उस महीने की शुरुआत में जिनेवा में व्यापार युद्धविराम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया था। अमेरिकी कंपनी कैडेंस और सिनोप्सिस ने कहा है कि वे चीन में पहले प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर की पहुंच बहाल करने की प्रक्रिया में हैं। वहीं, सिनोप्सिस ने अपने सॉफ्टवेयर और तकनीक की पूरी पहुंच फिर से बहाल कर दी है और चीन में बिक्री और समर्थन दोबारा शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार चिप-डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या ईडीए सॉफ्टवेयर पर वाशिंगटन के निर्यात नियंत्रण से चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वे नए माइक्रोचिप्स बनाने के लिए आवश्यक हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी इथेन उत्पादकों को भी चीन को निर्यात फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के आंकड़ों के आधार पर पिछले साल अमेरिका के इथेन निर्यात का लगभग 50% हिस्सा चीन को गया था। इस उपयोग मुख्य रूप से प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा, अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अन्य कंपनियों के साथ-साथ जीई एयरोस्पेस को भी चीन को जेट इंजन की शिपमेंट फिर से शुरू करने के लिए कहा है। शुक्रवार को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि चीन अब इन प्रतिबंधित वस्तुओं की निर्यात लाइसेंसिंग प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है। प्रवक्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका-चीन आर्थिक और व्यापार संबंधों के पारस्परिक लाभ को गंभीरता से समझेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ना जारी रखेंगे।

लंदन में पार्टी करते दिखे विजय माल्या और ललित मोदी, आर्थिक घोटालों को लेकर भागते फिर रहे दोनों कारोबारी

नई दिल्ली । भगोड़े अरबपति ललित मोदी और विजय माल्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों साथ में नाचते-गाते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो ललित मोदी ने ही अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो क्लिप में दोनों को फ्रैंक सिनात्रा का माई वे गाना गाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो लंदन का बताया जा रहा है और इस पार्टी में दुनियाभर के 300 से ज्यादा चुनिंदा लोगों को ही इनवाइट किया गया था। उपस्थित लोगों में वेस्टइंडिज के पूर्व क्रिकेटर क्रिस गेल का नाम भी शामिल थे। क्रिस ने मोदी और माल्या दोनों के साथ अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, हम इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं । एक शानदार शाम के लिए धन्यवाद। साथ ही क्रिस ने दोनों को टैग किया। मोदी ने वीडियो शेयर करके लिखा कि इस पार्टी में बहुत से लोग विशेष रूप से यात्रा करके आए थे। इस शाम में शामिल होने वाले और इसे मेरे लिए सबसे खास रातों में से एक बनाने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है कि यह वीडियो इंटरनेट पर धूम नहीं मचाएगा। निश्चित रूप से यह विवादास्पद है। लेकिन यही वह काम है जो मैं सबसे अच्छा करता हूं । इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के संस्थापक ललित मोदी पर वित्तीय गड़बड़ियों के कई आरोप लगे हैं। मोदी ने 2010 में भारत छोड़ दिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोदी के खिलाफ कई मामले चलाए हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, बोली में हेरफेर और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से संबंधित आरोप शामिल हैं। भारत ने बार-बार ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है, लेकिन वे अभी भी ब्रिटिश निवासी हैं। मोदी 60 वर्ष के हो चुके हैं और उनका कहना है कि उनपर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। यूनाइटेड

ब्रूअरीज के पूर्व चेयरमैन और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर 68 वर्षीय विजय माल्या पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। विजय माल्या को भारत ने साल 2019 में भगोड़ा घोषित कर दिया था। माल्या पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर 9 हजार करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है। पिछले सप्ताह, यूके के उच्च न्यायालय ने 2021 के दिवालियापन आदेश के खिलाफ माल्या की अपील को खारिज कर दिया था। पिछले साल एक सोशल मीडिया पोस्ट में माल्या ने कहा था कि भारत में अधिकारियों ने उनकी 14,131 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर उसे बहाल कर दिया है। उनके अनुसार यह राशि किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए ऋण से भी अधिक है। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि मैं अभी भी एक आर्थिक अपराधी हूं। जब तक ईडी और बैंक कानूनी रूप से यह साबित नहीं कर देते कि उन्होंने दोगुने से अधिक कर्ज कैसे लिया है, तब तक मैं राहत पाने का हकदार हूं और मैं इसके लिए प्रयास करूंगा।

आंकड़े : इस साल अब तक 25 कंपनियों के आईपीओ लिस्ट, संभव और क्वाड्रांट ने निवेशकों को किया मालामाल

नई दिल्ली । घरेलू बाजार के अप्रैल के बाद से रफ्तार पकड़ने से आईपीओ बाजार भी तेजी में है। इस साल कुल 25 कंपनियां आईपीओ लाई हैं और उसमें से 19 कंपनियों ने निवेशकों को रिटर्न दिया है। इनमें से क्वाड्रांट और संभव स्टील फायदा देने में शीर्ष पर है। हालांकि, 6 कंपनियों के शेयरों में निवेशकों को घाटा भी हुआ है। एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल जिन आईपीओ के शेयरों ने सबसे अधिक फायदा दिया है, उनमें क्वाड्रांट फ्यूचर 53 फीसदी के साथ शीर्ष पर है। इसका इश्यू का भाव 290 रुपये था और 444 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ था। संभव स्टील का भी शेयर 34 फीसदी ऊपर लिस्ट हुआ। 82 रुपये के भाव वाला इश्यू 110 रुपये पर लिस्ट हुआ था। इनके अलावा, जिन कंपनियों ने अच्छा फायदा दिया, उनमें लक्ष्मी डेंटल के शेयर ने करीब 29 फीसदी का रिटर्न दिया। इंडोफार्म का 215 रुपये का शेयर 277 रुपये पर लिस्ट हुआ था, यानी 29 फीसदी का फायदा मिला था। एलनबैरी के शेयर ने 33 फीसदी फायदा दिया। ग्लोब सिविल के शेयर ने भी निवेशकों को 33 फीसदी रिटर्न दिया। एचडीबी फाइनेंशियल ने एक हफ्ते में 13 फीसदी रिटर्न दे दिया। इसका इश्यू भाव 740 रुपये था और बुधवार को यह 853 रुपये पर लिस्ट हुआ था। आईपीओ बाजार में भारत इस समय दूसरे नंबर पर है। इस साल भारत ने 5.86 अरब डॉलर जुटाए हैं, जो वैश्विक आईपीओ बाजार का 12 फीसदी हिस्सा है। इस साल बड़े आईपीओ में एलजी का 15,000 करोड़ है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट भी अगस्त तक बाजार में उतरने की तैयारी में है। इस साल 143 आईपीओ 26 अरब डॉलर जुटाने वाले हैं। इस साल कई बड़े आईपीओ आने वाले हैं। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई का इश्यू 50,000 करोड़ रुपये से ऊपर हो सकता है। इसका मूल्यांकन 6 लाख करोड़ रुपये आंका गया है।

सीसीआई के आदेश की समीक्षा कर उचित कानूनी कदम उठाएंगे : एशियन पेंट्स

नई दिल्ली । एशियन पेंट्स निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई के उसके खिलाफ पारित आदेश की समीक्षा करने के साथ ही उचित कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पेंट के विनिर्माण और बिक्री के लिए बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का कथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए एशियन पेंट्स के खिलाफ जांच का आदेश दिया। यह निर्देश ग्रासिम इंडस्ट्रीज (बिरला पेंट्स की इकाई) की शिकायत के बाद दिया गया है। शिकायत में एशियन पेंट्स पर भारतीय पेंट क्षेत्र में इसके प्रवेश और विकास को बाधित करने से जुड़ी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया

गया है। एशियन पेंट्स ने कहा कि वह आरोपों की जांच में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ सहयोग करेगी। कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में एशियन पेंट ने कहा, ''वह वर्तमान में आदेश की समीक्षा कर रही है और उचित कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करेगी। कंपनी जांच के दौरान सीसीआई के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीसीआई ने इस सप्ताह की शुरुआत में पारित आदेश में कहा, ''आयोग की राय है कि वर्तमान मामले में एशियन पेंट्स द्वारा अधिनियम की धारा चार के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा चार बाजार में दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करती है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने महानिदेशक को मामले की जांच करने और 90 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ग्रासिम ने पिछले साल फरवरी में बिड़ला ओपस पेंट्स ब्रांड के तहत पेंट क्षेत्र में कदम रखा है। आदेश में स्पष्ट किया गया कि है कि ये टिप्पणियां मामले के गुण-दोष के आधार पर अंतिम राय नहीं है और महानिदेशक को निर्देश दिया गया कि वे इनसे प्रभावित हुए बिना जांच करें।

एसएमपीपी को भारतीय सेना से 300 करोड़ रुपए का मिला ठेका

मुंबई । रक्षा उपकरण विनिर्माता कंपनी एसएमपीपी लिमिटेड को भारतीय सेना से 300 करोड़ रुपए के दो ठेके मिले हैं। एसएमपीपी ने बयान में कहा कि इस ठेके के तहत कंपनी आपात प्रावधान के तहत भारतीय सेना को बुलेटप्रूफ जैकेट और उन्नत बैलिस्टिक हेलमेट की आपूर्ति करेगी। कंपनी ने कहा, ''एसएमपीपी भारतीय सेना को 27,700 बुलेटप्रूफ जैकेट और 11,700 उन्नत बैलिस्टिक हेलमेट की आपूर्ति करेगी। यह ठेका 300 करोड़ रुपए से अधिक का है।

एसएमपीपी के निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आशीष कंसल ने कहा, ''एसएमपीपी भारत में व्यक्तिगत सुरक्षा बाजार में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी (1लैटिस रिपोर्ट के अनुसार) के साथ अग्रणी रहा है, जो अनुसंधान एवं विकास पर इसके अत्यधिक ध्यान के कारण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि कंपनी ने पहले ही 17 से अधिक पेटेंट दाखिल किए हैं और 10 पेटेंट दिए जा चुके हैं। एसएमपीपी रक्षा उपकरणों का स्वदेशी विनिर्माता है। इसकी पलवल (हरियाणा) में एक विनिर्माण सुविधा है।

एक नजर

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी; बाद में उतार-चढ़ाव के बीच सपाट रुख

मुंबई । बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के दौरान बैंक शेयरों में खरीदारी और अमेरिकी बाजारों में तेजी के बीच थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि, बाद में बाजार में सपाट रुख देखने को मिला। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 67.34 अंक बढ़कर 83,306.81 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 23.55 अंक बढ़कर 25,428.85 पर पहुंच गया। बाद में दोनों प्रमुख सूचकांकों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा और वे सपाट कारोबार कर रहे थे। बीएसई बेंचमार्क 13.55 अंक गिरकर 83,221.65 पर और निफ्टी 4.15 अंक गिरकर 25,400.40 पर कारोबार कर रहा था।

किसे फायदा-किसे नुकसान?

सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख फायदे में दिखाई दिए। हालांकि, ट्रेंट, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और मारुति पिछड़ते नजर आए। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 1,481.19 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। डीआईआई ने 1,333.06 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

एशियाई और अमेरिकी बाजार का हाल

एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225 सूचकांक और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुआ। गुरुवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक दायरे में बंद हुए। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.42 प्रतिशत गिरकर 68.51 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

क्या कहते है विशेषज्ञ?

जियोजित इन्वेस्टमेंट के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, %निफ्टी की 25,200-25,800 की सीमा को तुरंत तोड़ने के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। इस सीमा के भीतर कारोबार करते हुए भी बाजार लचीला है। इस लचीलेपन को बाहरी तौर पर मदर मार्केट अमेरिका की मजबूती से समर्थन मिल रहा है, जहां एसएंडपी 500 और नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं।%

बीते दिन का हाल

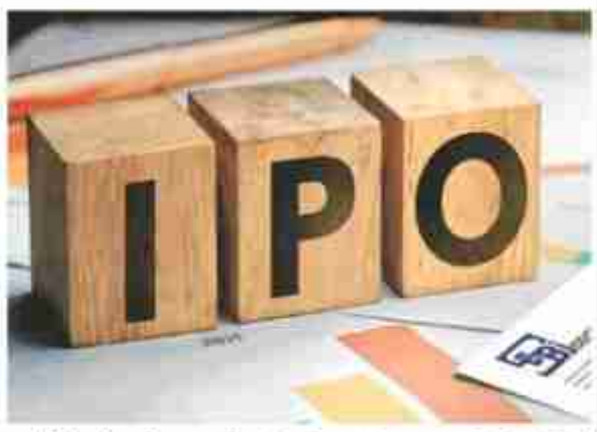

इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 170.22 अंक या 0.20 प्रतिशत गिरकर 83,239.47 पर बंद हुआ था। ऐसे ही निफ्टी 48.10 अंक या 0.19 प्रतिशत गिरकर 25,405.30 पर बंद हुआ था।

अब बिना शुल्क समय पूर्व चुका सकते हैं फ्लोटिंग दर वाले कर्ज, गैर-कारोबारी लोन पर 2026 से लागू होगा नियम

नई दिल्ली । अब प्रीपेमेंट के नाम पर भारी जुर्माना भरने से राहत मिलने वाली है। आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कहा है कि वे छोटे उद्यमों एवं व्यक्तिगत लोगों को दिए कर्ज पर समय से पूर्व भुगतान करने पर कोई शुल्क नहीं लगाएंगे। यह नियम एक जनवरी, 2026 के बाद लिए या नवीनीकरण कराए गए कर्जों पर लागू होगा। आरबीआई ने बुधवार को सर्कुलर में कहा, समीक्षाओं में पता चला है कि एमएसई को कर्ज का पहले भुगतान करने पर ज्यादा शुल्क देना होता है। इससे कर्जदाता संस्थान और ग्राहकों में विवाद पैदा होता है। कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने लोन एग्रीमेंट में ऐसे नियम बनाए हैं, जिससे उधार लेने वाला कम ब्याज या बेहतर शर्तों का लाभ उठाने के लिए अन्य संस्थान के पास नहीं जा सके। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के फ्लोटिंग दर पर लिए गए कर्ज पर कोई प्री पेमेंट शुल्क नहीं लगेगा। नया नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों (पेमेंट्स बैंकों को छोड़कर), सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होगा। आरबीआई ने कहा, इन नियमों के अंतर्गत न आने वाले मामलों में कोई पूर्व-भुगतान शुल्क है तो उसे कर्ज स्वीकृति पत्र और उसके समझौते में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। कोई भी अघोषित या पूर्व शुल्क की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ऋणदाता खुद पूर्व भुगतान शुरू करता है तो कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, नया नियम दोनों तरह के भुगतान पर लागू होगा। चाहे कर्जदार कर्ज का आंशिक या पूरा भुगतान करे। साथ ही, पुनर्भुगतान के लिए इस्तेमाल धन का स्रोत चाहे जो भी हो। इसके लिए बैंक या वित्तीय संस्थान कोई न्यूनतम लॉक-इन अवधि भी नहीं रख सकते हैं। इसका उद्देश्य ऋण देने की प्रथाओं को मानकीकृत करना और वित्तीय संस्थानों के बीच असंगत नीतियों के कारण उत्पन्न होने वाली ग्राहकों की शिकायतों को कम करना है।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि 10 माह के उच्च स्तर पर, नए कारोबार और निर्यात ऑर्डर में उछाल का असर

नई दिल्ली । मांग और बिक्री में जारी सुधार के बीच नए कारोबारी ऑर्डर में तेज उछाल के दम पर देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर जून, 2025 बढ़कर 10 महीने के उच्च स्तर 60.4 पर पहुंच गई। रोजगार सृजन में भी मजबूत विस्तार देखने को मिला। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस गतिविधि सूचकांक मई में 58.8 रहा था। एचएसबीसी इंडिया में मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, नए घरेलू ऑर्डर में अगस्त, 2024 के बाद सबसे तेज उछाल और नए निर्यात कारोबार में उल्लेखनीय तेजी से सेवा पीएमआई (खरीद प्रबंधक सूचकांक) 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। एशियाई, पश्चिम एशियाई एवं अमेरिकी बाजारों से आने वाली मांग में सुधार और घरेलू बाजार की निरंतर मजबूती से भी सेवा क्षेत्र की कंपनियों को लाभ हुआ। भंडारी ने कहा, सेवा क्षेत्र के निरंतर विस्तार का भर्तियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जून में लगातार 37वें महीने रोजगार बढ़ा है। मई की रिकॉर्ड भर्तियों से धीमी होने के बावजूद रोजगार वृद्धि की दर दीर्घकालिक औसत से आगे निकल गई। लागत का दबाव उपभोक्ता सेवा श्रेणी में सर्वाधिक रहा। आउटपुट शुल्क में तेज वृद्धि वित्तीय और बीमा क्षेत्र में रही। आउटपुट शुल्क के मुकाबले कच्चे माल की लागत में कम वृद्धि से सेवा प्रदाताओं के मार्जिन में सुधार हुआ।

4 जुलाई को महंगा हुआ सोना, चांदी 1,08,000 रुपए के पार

बिजनेस डेस्क । सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोने-चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत 0.31 फीसदी की तेजी के साथ 97,081 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी की कीमत 0.09 फीसदी की बढ़त के साथ 1,08,333 रुपए प्रति किग्रा पर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार चांदी के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सोने चांदी के वायदा भाव की शुरुआत नरमी के साथ हुई। सोना 3,335 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला क्लोजिंग प्राइस 3,342.90 डॉलर प्रति औंस था। खबर लिखे जाने के समय यह 4.30 डॉलर की गिरावट के साथ 3,338.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोने के वायदा भाव ने इस साल 3,509.90 डॉलर के भाव पर ऑल टाइम हाई छू लिया है। चांदी के वायदा भाव 37.05 डॉलर के भाव पर खुले। पिछला क्लोजिंग प्राइस 37.08 डॉलर था। खबर लिखे जाने के समय यह 0.22 डॉलर की गिरावट के साथ 36.86 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।